जशीर सिंह और रामेश्वर सिंह मलिक से पहले, जे जे.

मैसर्स मैजेस्टिक ऑटोकॉम्प प्राइवेट लिमिटेड लि.-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा

विकास निगम लि.

और अन्य-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपीनं. 2012 का 19017

24 सितंबर? 2012

भारत का संविधान 1950 - कला। 226 - रिट क्षेत्राधिकार - राज्य सरकार की औद्योगिक नीति, 2005 - संपदा प्रबंधन प्रक्रिया, 2005 - औद्योगिक विशेष परियोजना योजना का आवंटन 'जैसा है जहां है' के आधार पर कतार में कूदना - याचिकाकर्ता आवंटन के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहा - कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया लेकिन याचिकाकर्ता सुनवाई के अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा - प्लॉट फिर से शुरू हुआ - अपील तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश द्वारा खारिज कर दी गई - अनुबंध के खंड 5 के अनुसार कब्जे की पेशकश से दो साल के भीतर परियोजना पूरी की जानी है - याचिकाकर्ता द्वारा इसका पालन करने का वचन दिया गया ये नियम और शर्तें और सरकारी औद्योगिक नीति 2005 - एचएसआईआईडीसी द्वारा अनुस्मारक - परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिवादी - याचिकाकर्ता की ओर से भूखंड पर कब्जा लेने में विफलता - केवल भूखंड की कुल राशि जमा करने से याचिकाकर्ता का दायित्व समाप्त नहीं होता है, खासकर भूखंड आवंटित होने के बाद से विशेषाधिकारों के साथ विशेष योजना के तहत - याचिकाकर्ता एक ईमानदार और वास्तविक आवंटी नहीं था - बहाली का आदेश अवैधता से ग्रस्त नहीं है - रिट याचिका खारिज कर दी गई।

माना गया कि इन आधिकारिक संचारों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 1/2 साल की समाप्ति के बाद भी याद दिलाया गया था लेकिन वह संबंधित भूखंड पर कब्जा लेने में विफल

रहा। पत्र दिनांक 9.1एफ2.2009 से यह भी पता चलता है कि दिनांक 18.2.2009 का पत्र भी याचिकाकर्ता को लिखा गया था जिसमें टीएलसी समझौते की शर्तों और शर्तों के स्पष्ट उल्लंघन की ओर इशारा किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण से, हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता परियोजना की स्थापना के प्रति कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए केवल मामले में देरी करने में रुचि रखता था, समयबद्ध तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं, जैसा कि आवंटन पत्र और समझौते में निर्धारित है। इस प्रकार, विवादित बहाली आदेश और साथ ही अपीलीय आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

(पैरा 15)

इसके अलावा, यह माना गया कि याचिकाकर्ता के आकस्मिक दृष्टिकोण के कारण उत्पन्न हुई इस अनुचित स्थिति का सामना करने और कोई अन्य विकल्प नहीं बचे होने के कारण, प्रतिवादी प्राधिकारी ने दिनांक 8.11.2011 (अनुलग्नक पी-21) पर आक्षेपित बहाली आदेश पारित किया, जो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं है। अवैधता. याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि, टीआईसी आवंटन के पीसीआर नियमों और शर्तों के रूप में कटौती करने के बाद, दिनांक 13.12.2011 (अनुलग्नक पी -24) के पत्र के माध्यम से उसे वापस कर दी गई थी। इस मामले के इस दृष्टिकोण में, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विवादित बहाली आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही ढंग से पारित किया गया था। याचिकाकर्ता ने न केवल आवंटन/समझौते की शर्तों और शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया, बल्कि अनुबंध पी-4 में दिए गए अपने स्वयं के वचन का भी उल्लंघन किया।

(पैरा 20)

आगे कहा गया कि केवल प्लॉट के लिए कुल राशि जमा करने से याचिकाकर्ता का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। दोहराव की कीमत पर भी इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता को यह भूखंड एक विशेष योजना के तहत आवंटित किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता को अन्य आवेदकों की तुलना में कतार में कूदने की अनुमति मिलती है, याचिकाकर्ता को स्थापना के लिए अधिक सावधान और सतर्क रहना पड़ता है। निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना.

(पैरा 25)

इसके अलावा, यह माना गया कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता इस अवधि के दौरान अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने में विफल रहा है। यदि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की ओर से उठाए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो योजना का उद्देश्य और उद्देश्य विफल हो जाएगा। यह सामान्य आवंटन का मामला नहीं था. विचाराधीन भूखंड याचिकाकर्ता को एक विशेष योजना के तहत आवंटित किया गया था जिसमें उसे अन्य आवेदकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी थी। जब याचिकाकर्ता विशेष योजना के तहत उपलब्ध विशेषाधिकारों का दावा करने के लिए आवेदन करने के लिए आगे आया, तो याचिकाकर्ता आवंटन के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए भी बाध्य था।

याचिकाकर्ता को केवल एक विशेष योजना के तहत विशेषाधिकारों का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, पूरी तरह से उसी योजना से आने वाले उसके दायित्वों की अनदेखी की जा सकती है।

(पैरा 27)

अमित झांजी, अधिवक्ता/या याचिकाकर्ता।

रामेश्वर सिंह मलिक जे.

(1) वर्तमान रिट याचिका दिनांक 29.8.2012 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी गई थी और दिनांक 8.11.2011 को फिर से शुरू करने के आदेश को बरकरार रखा गया था।

(2) मामले की प्रासंगिक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि, इसमें शामिल मुद्दे के निपटान के लिए आवश्यक है, कि याचिकाकर्ता को सेक्टर 4, चरण II, औद्योगिक एस्टेट, जीसी में प्लॉट नंबर 204 आवंटित किया गया था। बावल, जिला रेवाडी, क्षेत्रफल 10104.27 वर्ग मीटर। यह भूखंड याचिकाकर्ता को एक चालू प्रतिष्ठित परियोजना योजना के तहत नियमित पत्र आवंटन दिनांक 3.4.2008 (अनुलग्नक पी-2) के माध्यम से ऑटो घटकों के निर्माण के लिए परियोजना स्थापित करने के लिए आवंटित किया गया था। यहां यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता को भूमि फास्ट ट्रैक आधार पर आवंटित की गई थी, जिसमें आवेदक को भूखंडों के आवंटन के लिए विज्ञापन का इंतजार नहीं करना पड़ा। आवंटन एक विशेष योजना के तहत किया गया था, जिससे याचिकाकर्ता को अन्य इच्छुक उद्यमियों की तुलना में कतार में कूदने

की अनुमति मिली, जो गैर-प्रतिष्ठित श्रेणी के तहत ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने की योजना बना रहे थे।

(3) याचिकाकर्ता को एचएसआईआईडीसी-प्रतिवादी नंबर 1 की राज्य सरकार की औद्योगिक नीति-2005 और संपदा प्रबंधन प्रक्रिया-2005 (संक्षेप में 'ईएमपी') के तहत कुछ नियमों और शर्तों के अधीन भूखंड आवंटित किया गया था।

(4) आवंटन पत्र के अनुसार पार्टियों के बीच निष्पादित समझौते के खंड 3 के अनुसार, भूखंड "जैसा है जहां है" के आधार पर आवंटित किया गया था। जब याचिकाकर्ता आवंटन के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहा, तो भूखंड को फिर से शुरू करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिनांक 3.5.2011 (अनुलग्नक पी-14) जारी किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा इसका जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को 30.8.2011, 2.9.2011 और 20.9.2011 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। फिर भी, याचिकाकर्ता को 18.10.2011 को उपस्थित होने का एक और अवसर दिया गया। चूँकि साइट निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 14.10.2011 के अनुसार, प्लॉट अभी भी खाली पाया गया था, दिनांक 8.11.2011 को आक्षेपित पुनर्ग्रहण आदेश, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित किया गया था।

(5) पुनः आरंभ आदेश दिनांक 8.11.2011 से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की। कंपनी के निदेशकों में से एक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ और उसे सुनवाई का अवसर दिया गया। याचिकाकर्ता की अपील बिना किसी तथ्य के पाई गई और उसे अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 29.8.2012 (अनुलग्नक पी-28) के आदेश के तहत खारिज कर दिया, जिससे बहाली आदेश बरकरार रखा गया।

(6) उपरोक्त बहाली आदेश के साथ-साथ अपीलीय आदेश, (क्रमशः अनुबंध पी-21 और अनुबंध पी-28) के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने तत्काल रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि चूंकि प्रश्न में भूखंड की माप उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना बहुत बाद के चरण में की गई थी, पत्र दिनांक 11.8.2010 (अनुलग्नक पी-9) के तहत, टीएलसी बहाली आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि जिस अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को निर्माण करना था और विनिर्माण प्रक्रिया शुरू करनी थी, उसकी गणना वास्तविक कब्जे की तारीख से की जानी चाहिए, न कि कब्जे की पेशकश से। ऐसी स्थिति में वास्तविक कब्ज़ा सौंपने के तुरंत बाद निर्माण न होने के आधार पर प्लॉट पर दोबारा कब्ज़ा करना, प्रथम दृष्टया अवैध था।

(8) याचिकाकर्ता के वकील ने अगली दलील दी कि चूंकि प्लॉट में ट्यूबवेल पंप और मजार थे और साथ ही हाई टेंशन तार भी प्लॉट के ऊपर से गुजर रहे थे, इसलिए प्रतिवादी-निगम इन्हें हटाने के लिए बाध्य था, जो उनके पास है। करने में असफल रहा.

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला कि चूंकि याचिकाकर्ता ने प्रश्नगत भूखंड की कुल राशि जमा कर दी थी, इसलिए इसे केवल इस कारण से फिर से शुरू नहीं किया जाना चाहिए था कि याचिकाकर्ता आवंटन के नियमों और शर्तों का पालन नहीं कर सका, जबकि उठा नहीं रहा था। समय पर निर्माण और उत्पादन शुरू करना।

(9) अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील 26.3.2012 के फैसले पर भरोसा करते हैं, जो इस न्यायालय द्वारा 2012 की सिविल रिट याचिका संख्या 6045 (मैसर्स लॉस एंजिल्स फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड बनाम हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर) में पारित किया गया था। विकास निगम और अन्य)

(10) हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(11) उठाए गए विवादों पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद और वर्तमान मामले की विशिष्ट तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम इस विचार पर सहमत हैं कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार

को लागू करने के लिए मामला बनाने में विफल रहा है। . हम ऐसा एक से अधिक कारणों से कहते हैं, जिन्हें आगे दर्ज किया जा रहा है।

(12) सबसे पहले, यह रिकॉर्ड पर एक निर्विवाद स्थिति है कि प्रश्न में भूखंड के आवंटन के अनुसार, अनुबंध पी-2 दिनांक 3.4.2008 के तहत, उन्होंने प्रतिवादी निगम, vidcअनुलग्नक पी-3 के साथ एक समझौता किया। समझौते के खंड 3 के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्लॉट "जैसा है जहां है" के आधार पर आवंटित किया गया था। आवंटी को कब्जे की पेशकश की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर परियोजना को लागू करना आवश्यक था। परियोजना के कार्यान्वयन का मतलब संयंत्र और मशीनरी की स्थापना के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा। यहां समझौते के विशिष्ट नियमों और शर्तों पर ध्यान देना उचित है, विशेष रूप से समझौते के खंड 5 के तहत प्रदान की गई समय-सारिणी और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए: -

"प्लॉट पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित तीन साल की अवधि के बावजूद, आवंटी को निम्नलिखित मानदंडों का पालन करना होगा:

(ए) उस आवंटी को भूखंड पर कब्जा लेने, भवन योजना जमा करने और आवंटन के छह महीने के भीतर साइट पर निर्माण शुरू करने की आवश्यकता होगी।

(बी) आबंटिती को आबंटन के एक वर्ष के भीतर कम से कम प्लिंथ स्तर तक निर्माण करना होगा।

(सी) आवंटी को परियोजना को पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यक निर्माण पूरा करना होगा और दो साल के भीतर संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए समझौते को अंतिम रूप देना होगा।

(डी) आबंटिती को आवंटन के तीन साल के भीतर परियोजना रिपोर्ट के अनुसार अनुमेय कवर क्षेत्र का कम से कम 25% निर्माण करने और परियोजना में अचल पूंजीगत संपत्ति (न्यूनतम 30 करोड़ रुपये) में निवेश बढ़ाने के बाद परियोजना को लागू करना होगा और दस्तावेज जमा करना होगा। इस संबंध में निगम को.

परियोजना के कार्यान्वयन और न्यूनतम रु. के निवेश के लिए उपलब्ध अनुसूची/समय का पालन करने में आवंटी की ओर से विफलता पर। परियोजना में 30 करोड़ रुपये की अचल पूंजी संपत्ति, एचएसआईआईडीसी उपरोक्त भूखंड को फिर से शुरू करने के लिए सक्षम होगी। "

(13) यह याचिकाकर्ता का स्वयं का मामला है कि उसने अपने पत्र दिनांक 2.6.2008 (अनुलग्नक पी-4) के माध्यम से, खुद को सरकार की औद्योगिक नीति-2005 के बारे में पूरी तरह से जागरूक होने की बात स्वीकार करते हुए, उपरोक्त नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन दिया था। और एचएसआईआईडीसी का ईएमपी भी। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए वचन के प्रासंगिक भाग को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: -

"1/हमने आरएलए के साथ-साथ परिशिष्ट ए के रूप में संलग्न प्रारूप में शामिल नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ा है। मैं/हम राज्य सरकार की औद्योगिक नीति, 2005 और एस्टेट प्रबंधन प्रक्रिया से भी अवगत हैं- एचएसआईआईडीसी की 2005 (ईएमपी)। मैं/हम एतद्द्वारा प्लॉट हो का आवंटन स्वीकार करते हैं। 204 सेक्टर/ब्लॉक/चरण 04, चरण II, औद्योगिक एस्टेट, जीसी.बावल में 10104.27 वर्ग मीटर (लगभग वास्तविक माप के अधीन) की माप, आरएलए में निहित नियमों और शर्तों पर ऑटो घटकों के निर्माण की एक औद्योगिक परियोजना स्थापित करने के लिए और परिशिष्ट ए यहां ऊपर उल्लिखित है और समय-समय पर संशोधित आईपी और ईएमपी के प्रावधानों का पालन करने का वचन देता है।

मैं/हम आरएलए के जारी होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर पंचकुला में एचएसएचडीसी के साथ आरएलए के साथ अनुबंध-ए के रूप में संलग्न समझौते के प्रारूप के अनुसार समझौते को निष्पादित करने का वचन देते हैं। ”

(14) यह ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस अवधि के दौरान, प्रतिवादी-अधिकारी याचिकाकर्ता को प्रश्नगत परियोजना की स्थापना के प्रति उसके आकस्मिक दृष्टिकोण के बारे में याद दिलाते रहे, जो दिनांक 25.9.2009 के संचार से स्पष्ट है (अनुलग्नक पी) -6) एवं दिनांक 9.12.2009 (अनुलग्नक पी-7)।

(15) इन आधिकारिक संचारों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 1'ए वर्ष की समाप्ति के बाद भी याद दिलाया गया था, लेकिन वह संबंधित भूखंड पर कब्जा लेने में विफल रहा। पत्र दिनांक 9.12.2009 से यह भी पता चलता है कि दिनांक 18.2.2009 को भी याचिकाकर्ता को पत्र लिखा गया था जिसमें समझौते के नियमों और शर्तों के स्पष्ट उल्लंघन की ओर इशारा किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण से, हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता परियोजना की स्थापना के प्रति कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए केवल मामले में देरी करने में रुचि रखता था, समयबद्ध तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं, जैसा कि आवंटन पत्र और समझौते में निर्धारित है। इस प्रकार, विवादित बहाली आदेश और साथ ही अपीलीय आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

(16) दूसरे, प्रेजेंटऑन ऐसा मामला नहीं है जिसमें यह आरोप लगाया जा सके कि याचिकाकर्ता को आक्षेपित पुनर्ग्रहण आदेश के साथ-साथ अपीलीय आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया था। परिशिष्ट पी-13 के तहत याचिकाकर्ता को दिनांक 14.1.2011 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता को 30 दिनों की अवधि के भीतर कारण बताने के लिए कहा गया था, ऐसा न करने पर निगम के पास नियम और शर्तों के अनुसार बहाली की कार्यवाही शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हालाँकि, याचिकाकर्ता कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में विफल रहा।

(17) इसके बाद, याचिकाकर्ता को एक और कारण बताओ नोटिस दिनांक 3.5.2011 (अनुलग्नक पी-14) जारी किया गया, जिससे उसे 30 दिनों के भीतर कारण बताने का एक और अवसर दिया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि दिनांक 18.8.2011 के पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता को 2.9.2011 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया था, ताकि वह समय पर परियोजना के कार्यान्वयन न होने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके, लेकिन वह फिर से विफल रहा। के जैसा लगना। इसके बाद, पत्र दिनांक 6.9.2011 (अनुलग्नक पी-16) के माध्यम से, याचिकाकर्ता को 20.9.2011 को संपदा प्रबंधन समिति (संक्षेप में 'ईएमसी') के समक्ष उपस्थित होने का एक और अवसर दिया गया था।

(18) यहां यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि पत्र दिनांक 17.8.2011 (एसआईसी) 17.9.2011 के तहत, याचिकाकर्ता ने 2.9.2011 को व्यक्तिगत सुनवाई में शामिल नहीं होने के लिए माफी मांगी, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता कंपनी का सक्षम व्यक्ति भारत से बाहर था। . आगे कहा गया कि जब भी सक्षम व्यक्ति भारत आएगा, याचिकाकर्ता प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम के साथ ठोस प्रस्ताव के साथ ईएमसी के समक्ष उपस्थित होगा। प्रतिवादी ने दिनांक 3.10.2011 के पत्र (अनुलग्नक पी-19) के माध्यम से 18.10.2011 को याचिकाकर्ता को सुनवाई का एक और अवसर दिया और उसके जवाब में, याचिकाकर्ता द्वारा 18.10.2011 को प्रतिवादी को एक पत्र भेजा गया (अनुलग्नक पी) -20), अभी और समय मांग रहा हूं।

(19) याचिकाकर्ता कंपनी का प्रतिनिधि 18.10.2011 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन वह इस संबंध में अधिक समय की मांग करते हुए याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से उठाए गए आधार को प्रमाणित करने में विफल रहा। दरअसल, याचिकाकर्ता कंपनी परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में कोई निश्चित योजना नहीं दिखा सकी.

(20) याचिकाकर्ता के आकस्मिक दृष्टिकोण के कारण बनी इस अनुचित स्थिति का सामना करते हुए और कोई अन्य विकल्प नहीं बचा होने पर, प्रतिवादी प्राधिकारी ने दिनांक 8.11.2011 (अनुलग्नक पी-21) पर आक्षेपित बहाली आदेश पारित किया, जो किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है। . याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि, आवंटन की शर्तों और शर्तों के अनुसार कटौती के बाद, दिनांक 13.12.2011 (अनुलग्नक पी -24) के पत्र के माध्यम से वापस कर दी गई थी। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि विवादित बहाली आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही ढंग से पारित किया गया था। याचिकाकर्ता ने न केवल आवंटन/समझौते की शर्तों और शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया, बल्कि vidcAnncxurc P-4 में दिए गए अपने स्वयं के वचन का भी उल्लंघन किया।

(21) तीसरा, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया। उपरोक्त बहाली के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान भी, याचिकाकर्ता को उचित अवसर दिया गया था जो दिनांक 13.3.2011 के संचार (अनुलग्नक पी-26) से स्पष्ट है। अपीलीय प्राधिकारी ने पहले भी मामले के हर भौतिक पहलू पर

चर्चा की है एक विवेकपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि याचिकाकर्ता की अपील में कोई योग्यता नहीं थी और कोई तथ्य नहीं था। तदनुसार, याचिकाकर्ता की अपील दिनांक 29.8.2012 (अनुलग्नक पी-28) के एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करके खारिज कर दी गई। जहां तक प्रश्नगत भूखंड की माप के संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील का सवाल है, यह है

पहली नजर में गलत धारणा। प्लॉट के क्षेत्रफल में अंतर नाम मात्र का था। मूल रूप से आवंटित भूखंड की माप 10104.27 वर्ग मीटर थी, जबकि स्थल पर माप करने पर इसका क्षेत्रफल 10120 वर्ग मीटर अर्थात मूल आवंटित क्षेत्रफल से 15.73 वर्ग मीटर अधिक पाया गया, जो कि पत्रावली दिनांक 11.8 से स्पष्ट है। .2010 (अनुलग्नक पी-9)।

(22) यह तर्क करने के लिए अपील नहीं करता है कि भूखंड के क्षेत्र में यह नगण्य अंतर, याचिकाकर्ता के लिए आवंटन की शर्तों और शर्तों का उल्लंघन करने का आधार कैसे हो सकता है, इसके दिनांक 2.6.2008 के वचन के बावजूद (अनुलग्नक पी-) 4), खासकर जब आवंटन "जैसा है जहां है" के आधार पर किया गया था। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि कब्जे की तारीख की गणना याचिकाकर्ता को वास्तविक कब्जा सौंपने से की जानी चाहिए थी, न कि कब्जे की पेशकश से, बिना किसी बल के है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आवंटन के तुरंत बाद कब्जा लेने के लिए आगे आना याचिकाकर्ता के लिए अनिवार्य था। जब याचिकाकर्ता इस संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, तो उत्तरदाताओं को दिनांक 25.9.2009, 9.12.2009 (अनुलग्नक पी-6 और पी-7) के माध्यम से याचिकाकर्ता को बार-बार याद दिलाना पड़ा। याचिकाकर्ता को बताया गया कि भूखंड का भौतिक कब्ज़ा 3.4.2008 से प्रभावी किया गया था और मामले के इस तथ्यात्मक पहलू को याचिकाकर्ता द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी।

(23) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया अगला तर्क कि प्रश्नाधीन भूखंड से ट्यूबवेल, पंप, पीपल के पेड़, मजार आदि को हटाना प्रतिवादी अधिकारियों का काम था, फिर भी सरल लेकिन मजबूत के लिए कोई सार नहीं है। कारण कि याचिकाकर्ता को "जहाँ है जैसा है" के आधार पर आवंटन किया गया था। वास्तव में, याचिकाकर्ता ने किसी भी प्रासंगिक समय पर इस मुद्दे को नहीं उठाया। इसके अलावा, हमें इसका कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता ने संबंधित भूखंड से ट्यूबवेल, पंप, पीपल

के पेड़, मजार आदि को क्यों नहीं हटाया। इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। इस प्रकार, चूंकि इस विवाद में भी कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(24) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया अंतिम तर्क यह भी है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने प्रश्नगत भूखंड की कुल राशि जमा कर दी थी, इसलिए आवंटन पत्र के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण पुनर्ग्रहण आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था। पूरी तरह से गलत जगह पर. दोनों पक्षों के बीच समझौते के खंड 5 के तहत प्रदान की गई शर्तों के अनुसार, जो ऊपर प्रस्तुत किया गया है, याचिकाकर्ता की ओर से यह अनिवार्य था,

संबंधित भूखंड पर परियोजना को निश्चित समय सीमा के भीतर स्थापित करना। याचिकाकर्ता आवंटन के विशिष्ट और स्पष्ट नियमों और शर्तों का पालन करने में पूरी तरह विफल रहा।

(25) केवल प्लॉट की कुल राशि जमा कर देने से याचिकाकर्ता का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। दोहराव की कीमत पर भी इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता को यह भूखंड एक विशेष योजना के तहत आवंटित किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता को अन्य आवेदकों की तुलना में कतार में कूदने की अनुमति मिलती है, याचिकाकर्ता को स्थापना के लिए अधिक सावधान और सतर्क रहना पड़ता है। निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जिस फैसले पर भरोसा किया, उससे याचिकाकर्ता को कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से अलग है।

(26) उद्धृत निर्णय में, मूल रूप से आवंटित भूखंड की माप 21600 वर्ग मीटर थी जबकि वास्तविक माप पर यह 22860 वर्ग मीटर पाया गया। इस प्रकार 1260 वर्ग मीटर का अंतर पाया गया। इसके अलावा, उद्धृत मामले में तथ्य प्रस्तुत मामले से बिल्कुल अलग थे। यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि किसी भी संहिताबद्ध या निर्णय-निर्मित कानून को लागू करने से पहले, प्रत्येक मामले की विशिष्ट तथ्य स्थिति पर पहले विचार किया जाना चाहिए और उसकी सराहना की जानी चाहिए।

(27) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता इस अवधि के दौरान अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने में विफल रहा है। यदि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की ओर से उठाए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो

योजना का उद्देश्य और उद्देश्य विफल हो जाएगा। यह सामान्य आवंटन का मामला नहीं था. 'याचिकाकर्ता को प्लॉट एक विशेष योजना के तहत आवंटित किया गया था, जिसमें उसे अन्य आवेदकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी थी। जब याचिकाकर्ता विशेष योजना के तहत उपलब्ध विशेषाधिकारों का दावा करते हुए आवेदन करने के लिए आगे आया, तो याचिकाकर्ता आवंटन की शर्तों और शर्तों का पालन करने के लिए भी बाध्य था। यानी याचिकाकर्ता को किसी विशेष योजना के तहत केवल विशेषाधिकारों का दावा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, वह पूरी तरह से उसी योजना से आगे बढ़ते हुए अपने दायित्वों की अनदेखी कर रहा है।

(28) अंतिम तर्क का दूसरा भाग यह है कि याचिकाकर्ता को परिपत्र दिनांक 16.7.2009, अनुलग्नक पी-5 के लाभ से वंचित कर दिया गया था, हालांकि पहली नज़र में यह आकर्षक लगता है, फिर भी जब मामले के तथ्यों की समग्रता पर विचार किया जाता है तो यह बिना किसी तथ्य के है। .Acarefi.il विवादित पुनर्ग्रहण आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि 3'ए लंबे वर्षों की समाप्ति के बावजूद, भूखंड खाली पड़ा था। दसियों के स्पष्ट उल्लंघन को देखते हुए और बहाली आदेश में क्रम संख्या 2,3 और 4 पर उल्लिखित शर्तों के अनुसार, आदेश न केवल मामले के तथ्यों पर बल्कि कानून में भी सही और पूरी तरह से उचित था। कोई भी घड़ी को पीछे नहीं कर सकता था। याचिकाकर्ता किसी और को नहीं बल्कि खुद को दोषी मानता था याचिकाकर्ता सहानुभूति का हकदार नहीं है और न ही हम अपने फैसले को प्रभावित करने के लिए अपनी सहानुभूति का प्रयोग करने के इच्छुक हैं। इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को एमए टेरी ओट एस्टेट्स (पी) लिमिटेड बनाम यू.टी., चंडीगढ़ और अन्य (1) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से समर्थन मिलता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ टेरी ओट के मामले (सुप्रा) में पैरा संख्या 36 से 39 में, जिसका वर्तमान मामले में लाभप्रद रूप से पालन किया जा सकता है, निम्नानुसार पढ़ें: -

सहानुभूति:

36 . हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि सहानुभूति या भावना अपने आप में उस संबंध में आदेश पारित करने का आधार नहीं हो सकती है, जिसके संबंध में अपीलकर्ता कानूनी अधिकार स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहते हैं। यह और भी घृणित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 में निहित एक असाधारण संवैधानिक क्षेत्राधिकार के बावजूद, यह न्यायालय आमतौर पर कोई आदेश पारित नहीं करेगा, जो वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन होगा।

3 7. 1911 में ही, फेयरवेल एल. लैथम बनाम रिचर्ड जॉनसन में जे

6 नेफ्यू लिमिटेड, (1911-13 एईआर पुनर्मुद्रण पृष्ठ 117) देखा गया:

"हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम अपनी सहानुभूति को शिशु वादी के साथ हमारे निर्णय को प्रभावित न करने दें। भावना कानूनी सिद्धांतों की खोज में एक मार्गदर्शक के रूप में लेने के लिए एक खतरनाक इच्छाशक्ति है। "

(अशोक साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य, सीएलटी (1999) 2 एच.सी 1 भी देखें)।

38. सैरिंध्री डडोलुई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2000) 1 एसएलआर 803 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच, जिसमें (हममें से एक सिन्हा, जे. सदस्य थे) ने उपरोक्त आदेश का पालन किया।

(1) (2004) 2 एससीसी 130

39. यह न्यायालय भी सी.बी.एस.ई. में है। और अन्य वी. पी. सुनील कुमार और अन्य, एफ1998] 5 एससीसी 377 ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई और सफल होने और उनके पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किए जाने से बहुत बड़ा अन्याय होगा, यह माना गया:

". . . हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि उच्च न्यायालय के विवादित निर्देशों को रद्द करने वाला हमारा आदेश इन छात्रों के साथ अन्याय होगा। लेकिन एक असंबद्ध संस्थान के छात्रों को न्यायालय के आदेश के तहत बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देना और फिर बोर्ड को परीक्षा देने वाले छात्रों के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मजबूर

करना कानून को तोड़ने के समान होगा और यह न्यायालय ऐसा करेगा। छात्रों के पक्ष में अनुचित सहानुभूति पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों को बरकरार रखना उचित नहीं होगा..."

(30) ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त कारणों के साथ, यह निःसंकोच माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा बार-बार पत्र, अनुस्मारक और कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद भी आवंटन के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है। . सुनवाई के बार-बार अवसर भी दिए गए। याचिकाकर्ता को विवादित बहाली आदेश के साथ-साथ अपीलीय आदेश पारित करने से पहले हर प्रासंगिक समय पर अपना मामला रखने का उचित अवसर दिया गया था।

(31) मामले के इस दृष्टिकोण में, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि याचिकाकर्ता एक ईमानदार और वास्तविक आवंटी नहीं था। यह उन कारणों से अधिक से अधिक समय प्राप्त करना चाहता था जो उसे सबसे अच्छे से ज्ञात थे, जिससे योजना का उद्देश्य ही विफल हो रहा था।

(32) याचिकाकर्ता की ओर से कोई अन्य तर्क नहीं उठाया गया।

(33) हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

(34) परिणामस्वरूप, तत्काल सिविल रिट याचिका को किसी भी योग्यता के बिना और बिना किसी तथ्य के पाए जाने पर, इसे खारिज करने का आदेश दिया जाता है।

एस गुप्ता

<u>अस्वीकरण:</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी

(Trainee Judicial

Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा